जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 322 प्रभात अजमेर, बुधवार 22 जून, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

रात्रि में होने वाला प्रकाश प्रदूषण मोनार्क तितली के आन्तरिक कॉम्पस को उलट सकता है और रास्ता ढूंढने की उसकी क्षमता में व्यवधान डाल सकता है। कृत्रिम प्रकाश, जैसे घर के पोर्च की लाइट, सड़क की लाइट, मोनार्क तितली की सर्केडियन रिद्म (शरीर की आंतरिक घड़ी की लय) को बाधित कर सकती है, जिससे मोनार्क तितलियां रास्ता भटक सकती हैं। युनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के सहायक प्रोफेसर और शोध लेखक पैट्रिक ग्वेरा ने कहा कि, तितलियों के लिए अंधेरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्केडियन क्लॉक तभी काम करती है जब तितलियाँ प्राकृतिक दिन-रात के चक्र के सम्पर्क में आती हैं, अंधेरे के बिना तितली की सर्केडियन क्लॉक काम नहीं कर सकती। हर साल लाखों की तादाद में मोनार्क तितलियां माइग्रेशन करती हैं और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से कैलिफोर्निया और मैक्सिको जाती हैं और वहां से लौटती हैं। लेकिन गलत समय पर बहुत सारा प्रकाश मिलने से तितलियां गलत समय पर उड़ने के लिए प्रेरित हो सकती हैं, जबकि उस समय उन्हें विश्राम करना चाहिए। ग्वेरा ने कहा, ''हमारा लक्ष्य यह समझना था कि, किस प्रकार मौजूदा पर्यावरणीय तनाव, जैसे शहरीकरण के कारण उत्पन्न विभिन्न प्रकार के तनाव, जानवरों के माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। शोध के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में तितली पर कृत्रिम रौशनी के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, तितली को फ्लाइट सिम्युलेटर (एक तरह का बटर फ्लाई ट्रैडमिल) पर रखा गया, जिस पर हम उनके उड़ान सम्बंधी व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। हमने उनका कृत्रिम प्रकाश से सामना करवाया। हमने देखा, जब अंधेरे में तितली को फ्लाइट सिम्युलेटर पर रखा गया तो वे शांत बैठी रहीं पर जैसे ही वैज्ञानिकों ने लाइट जलाई वे उड़ने लगीं, क्योंकि प्रकाश से संपर्क में आते ही उन्हें लगा कि दिन हो गया है। इस स्थिति में आने पर उन्हें रात में देर तक उड़ना पड़ सकता है या वे सुबह वे जल्दी उड़ना शुरु कर सकती हैं। ग्वेरा ने कहा कि, प्रकाश प्रदूषण, खासकर रात के समय के प्रकाश प्रदूषण के कारण जानवरों को ऐसे समय में दिन का अनुमान होने लगता है, जब असल में रात होती है और उस समय उन्हें आराम करना होता है। ये नतीजे जर्नल साईन्स में छपे हैं।

भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को चुना

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मु (59 वर्ष), जो ओडिशा की आदिवासी महिला नेता हैं, को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एन.डी.ए. का प्रत्याशी चुना गया है।

वे मई 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी थीं और पूरे 5 साल इस पद पर रहीं।

■ **मुर्मू, जो झारखण्ड की राज्यपाल थीं, तथा ओडिशा की आदिवासी महिला हैं, अब भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी।**

भाजपा के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में बाद घोषणा की कि, पहली बार आदिवासी महिला प्रत्याशी को प्राथमिकता दी गई है।

नड्डा ने कहा कि, हम आगामी राष्ट्रपति चुनावों में एन.डी.ए. प्रत्याशी के रूप में भाजपा द्रौपदी मुर्मु की उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं।

मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी व अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे।

यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी बने

यशवंत सिन्हा 1993 में भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा पार्टी में शामिल किये गये थे तथा अडवाणी खुद सिन्हा के ''संरक्षक'' रहे थे भाजपा में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। विपक्ष के नेता आज अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केन्द्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिये अपना सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाने के लिए सहमत हो गये।

इसे एक विडम्बना या परिस्थितियों का उलटफेर ही कहा जायेगा कि जिन सिन्हा को भाजपा के निर्माताओं में से एक एल.के. आडवाणी, जो देश के उपप्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा में लाये थे, वही सिन्हा आज सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं।

मुझे 1993 की वह प्रैस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, जिसमें आडवाणी ने सिन्हा के पार्टी में प्रवेश को ''दिवाली का उपहार'' बताया था। आडवाणी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ **अपनी जीवनी, ''रिलैन्टलैस'' में सिन्हा ने लिखा है कि, उनकी जन्म तिथि इतिहास की भूल भूलैया में कहीं ''खो'' गयी है, पर स्कूल रिकॉर्ड में उनका जन्म दिन 6 नवम्बर, 1937 दर्ज है।**

■ **सिन्हा, पोलिटिकल साइन्स में, पटना युनिवर्सिटी से एम.ए. करने के बाद 1960 में आई.ए.एस. बने, तथा 25 वर्ष के कार्यकाल में कई पदों पर रहने के बाद, केन्द्रीय सरकार में वित्त सचिव भी बने।**

■ **1987 में, जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर, सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर, राजनीति में कूदे, तथा 1986 में जनता पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए, तथा फिर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया।**

■ **1990 में चन्द्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री बने।**

■ **2018 में सिन्हा ने राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा की पर, फिर 2021 में प. बंगाल के विधानसभा चुनाव से पूर्व ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करते हुए, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तथा, उपाध्यक्ष का पद संभाला।**

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा?

-श्री नन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिव सेना के मंत्री एकनाथ शिन्दे के राज्य से गायब हो जाने के परिणाम स्वरूप, महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन के दौर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि शिन्दे, शिव सेना के कुछ विधायकों के साथ, गुजरात के सूरत शहर में डेरा डाले हुये हैं।

288 सदस्यीय विधान सभा (एक सीट खाली) में, किसी पार्टी या गठबंधन को सामान्य बहुमत के लिये 144 सीटें चाहिये। इस समय भाजपा के विधायकों की संख्या 106 है तथा भगवा पार्टी के लिये यह बड़ा मुश्किल होगा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एम.वी.ए. सरकार के गिरने की स्थिति में, इतने कम समय में बहुमत के आँकड़े तक पहुँचने की व्यवस्था कर सके। महाराष्ट्र विधानसभा में 16 निर्दलीय विधायक हैं, जिनमें से कई विधायक शिव सेना कोटा से मंत्री बने हुए हैं। यह भी अनिश्चित ही है कि शिन्दे को उतने विधायकों का समर्थन मिल जायेगा, जितने विधायकों की जरूरत, दलबदल-विरोधी कानून से बचने के लिये होगी।

भाजपा सूत्रों ने कहा कि इसलिये, अगर ठाकरे सरकार अपने निजी अन्तर्विरोधों के चलते गिर भी जाती है तो भाजपा सरकार बनाने के लिये अपना दावा प्रस्तुत करने के लिये कुछ समय चाहेगी। पिछले विधान सभा चुनावों के बाद, भाजपा का ''पैचवर्क'' सरकार का अनुभव उस समय बहुत ज्यादा खराब रहा था, जब देवेन्द्र फड्नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चन्द दिन के अन्दर ही इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच एम वी ए पार्टनर नुकसान को रोकने तथा उसकी भरपाई करने के लिये जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिन्दे से बातचीत करने के लिये अपना एक दूत सूरत भेज दिया है। एन सी पी नेता शरद पवार, जो आज दिल्ली में थे, देर शाम के समय मुम्बई लौट गये हैं, जहाँ वे एन सी पी विधायकों की मीटिंग लेंगे। कांग्रेस ने कमलनाथ को भेज दिया है, जिनके स्वयं के साथ यह विडम्बना रही कि जब वे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय वे ज्योतिरादित्य के नेतृत्व में होने वाली बगावत को नहीं भांप सके थे।

■ **शिव सेना के विधायकों की बगावत के बाद भी, भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में शायद बहुमत हासिल न कर पाये।**

शिव सेना अतीत में भी कई संकटों से सफलतापूर्वक गुजर चुकी है। 1991 में छगन भुजबल, जो इस समय महाराष्ट्र में मंत्री हैं, ने बगावत कर दी थी तथा शिवसेना (बी) पार्टी बना ली थी। इसके बाद, बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में पार्टी छोड़ कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। उसी साल, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अग्निपथ

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग की प्रतिक्रिया स्वरुप जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण अग्निपथ स्कीम वापस लिए जाने की संभावना से इंकार कर दिया।

बघेल ने कहा, पूरा देश इस योजना के विरोध में आंदोलन कर रहा है और यह देश के लोक-कल्याण के हित में नहीं है, युवा नाराज़ है। मु.मंत्री ने कहा,

■ **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने स्पष्ट किया, अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की कोई संभावना नहीं है।**

''भाजपा कह रही है वो उन्हें (4 वर्ष बाद रिटायर हो रहे युवाओं) ऑफिसों में चपरासी की नौकरी देगी। क्या केन्द्र ने क्लास फॉर के पद अभी से समाप्त कर दिए हैं। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।''

अग्निपथ योजना को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों हैशटैग अग्निपथ स्कीम पर एन.एस.ए. अजीत डोवाल ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिव सेना नेता व नगरीय विकास मंत्री शिंदे ने अपने 21 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी

मु.मंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से हटाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तीन पार्टियों की गठबंधन सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई क्योंकि वरिष्ठ मंत्री गत रात्रि सूरत चले गए और अपने साथ 21 विधायकों को भी ले गए उन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी है।

उद्धव ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की और उन्हें पार्टी के महत्वपूर्ण ''चीफ व्हिप'' (मुख्य सचेतक) पद से हटा दिया है। इधर शिंदे ने भी ट्विटर पर से शिव सेना में अपनी भूमिका का उल्लेख हटा दिया है।

शिंदे गुजरात के सूरत के एक रिसॉर्ट में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके नेतृत्व में जी-22 ऐसे राज्य में ठहरा है जहां भाजपा की सरकार है इसलिए इस बगावत के पीछे भाजपा की भूमिका उजागर होती है।

महाराष्ट्र का संकट कथित रुप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस की देन है, जो आज दिल्ली गए और अमित शाह से मिले फड़नवीस ने ही शिंदे के सूरत में ठहरने की व्यवस्था की है।

ठाकरे ने आज शाम ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई पर उसमें बहुत कम लोग थे। उन्होंने शिंदे को मुख्य सचेतक पद से हटा दिया।

ठाकरे की सरकार शिव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एन.सी.पी. के सहयोग से बनी थी। यह गठबंधन 2019 में पवार ने बनाया। इस संकट में उनकी भूमिका पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इस संकट में उनकी भी भूमिका है। क्योंकि पवार ने कहा है कि यह संकट शिव सेना का आंतरिक मामला है पर उन्हें कहा कि वे तीन पार्टी की सरकार के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

■ **शिंदे की बगावत में पूर्व मु.मंत्री फड़णविस की मुख्य भूमिका।**

■ **शिंदे की बगावत का तत्कालिक कारण गत रात्रि मु.मंत्री ठाकरे द्वारा शिंदे को लताड़ पिलाना बताया जाता है। ठाकरे की नाराज़गी का कारण शिव सेना के विधायकों द्वारा एम.एल.सी. के चुनाव में शिव सेना के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करना था। ठाकरे इस कृत्य के लिये शिंदे को जिम्मेवार मानते हैं।**

■ **पर, शिंदे काफी समय से शिव सेना के नेता संजय राउत को मु.मंत्री द्वारा दिये जा रहे महत्व से नाखुश भी थे।**

पवार ने सुबह यह भी कहा था कि वे शाम को बम्बई जाकर ठाकरे से मिलेंगे। सुबह वे दिल्ली में विपक्ष की एक मीटिंग में थे जिसमें यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशई घोषित किया गया।

यह संकट असल में ठाकरे द्वारा एकनाथ शिंदे को फटकारने से शुरु हुआ था क्योंकि सोमवार को हुए एक प्रमुख चुनाव में शिव सेना विधायकों ने भाजपा के लिए वोट क्रॉस वोटिंग की। उनकी इस हरकत की वजह से विधान परिषद की 10 में से 5 सीटें भाजपा जीत गई जबकि उसके हिस्से में सिर्फ चार सीटें ही आनी थीं।

शिंदे असल में शिव सेना में संजय राउत के बढ़ते दबदबे से नाखुश थे, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कमलनाथ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ गठबंधन, जहाँ इस समय राजनैतिक रूप से अशांत है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को वहाँ, अगले माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक के लिये पार्टी-पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है।

जिस अशान्ति से शिव सेना गुजर रही है, उससे कांग्रेस अप्रभावित बनी हुई है, लेकिन पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर परेशान है कि कांग्रेस को सोमवार को होने वाले विधान परिषद चुनावों में केवल एक ही सीट मिल रही है, जबकि विपक्षी दल भाजपा 5 सीटें जीत रहा है।

■ **महाराष्ट्र में चल रही उथल-पुथल में कांग्रेस को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी कमलनाथ को सौंपी गई है।**

लेकिन नैशनलिस्ट पार्टी प्रमुख शरद पवार, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) की शिव सेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गठन में ''किंग मेकर'' की भूमिका में थे, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'यूक्रेन को दीर्घकाल तक मदद देकर हम यूक्रेन की ही नहीं अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं'

नाटो के उच्चतम अधिकारी स्टोल्टेनबर्ग का यह भी कहना है कि, यूक्रेन को सहायता देकर हम विश्व को पुतिन जैसे लोगों के महत्वाकांक्षी व खतरनाक सपनों से बचायेंगे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन को एक लम्बे समय तक मजबूत समर्थन देकर ''हम तथा हमारे सहयोगी यूक्रेन के साथ ही अपनी खुद की भी सुरक्षा करेंगे और पुतिन तथा उनके जैसा काम करने के मंसूबे रखने वालों के घातक मंसूबों से दुनिया की रक्षा करेंगे।''

जॉनसन ने लिखा ''समय एक महत्वपूर्ण कारक है। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि रूस जब तक हमला करने की अपनी क्षमता को पुन: जुटाए तब तक क्या यूक्रेन उससे भी तीव्र गति से अपनी सरजमीं की रक्षा करने की क्षमता बढ़ा सकता हैं। हमारा काम यूक्रेन की समय पर मदद करना है।''

स्टोल्टेनबर्ग आशावादी थे कि युद्ध में यूक्रेन पासा पलट सकता है ''हालांकि दोन्बास को रूस बहुत क्रूरता से अपने अधिकार में लेने के प्रयास में है। लेकिन यूक्रेन के सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं। अधिक आधुनिक शस्त्रों के प्रयोग से संभावना यह बढ़ रही है कि यूक्रेन दोन्बास से एक बार फिर से पुतिन की सेना को खदेड़ने में कामयाब होगा।''

यूक्रेन की सेना सोवियत युग के गोला बारूद से लड़ रही है जो लड़ाई के पुराने सिस्टम में फिट बैठता है। जहां पश्चिमी हथियार सिस्टम यूक्रेन पहुंच रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ैलैन्स्की ने इस हफ्ते चेतावनी दी कि इनके शीघ्रता से पहुंचने की जरुरत है क्योंकि रुस ने पूर्वी यूरोप में उसके दो शहरों के आसपास तोपें तैनात कर एडवांटेज ले ली है।

अमेरिकी अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि लड़ाई के अग्रिम मोर्चे, पर पश्चिमी हथियार अब भी पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय खबरें इन हथियारों की कमी बता रही हैं और अग्रिम मोर्चे पर खड़े यूक्रेन के अधिकारी इन हथियारों की कमी की बड़े विचलित होकर शिकायत कर रहे हैं, जिससे इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पश्चिमी हथियारों की सप्लायी लाइन कितनी प्रभावी है?

■ **''हमारे प्रयत्नों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि, यूक्रेन कितनी जल्दी पश्चिमी देशों की सामरिक मदद से अपने आप को सुसज्जित कर लेता है, और किस स्पीड से रूस अपने नष्ट हो रहे हथियारों को नये हथियारों से ''रिप्लेस'' करता है।''**

बाइडन प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की कि वह यूक्रेन को एक अरब डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता उपलब्ध करवाएगा। इस पैकेज में होवित्जर्स, गोला बारुद और तटीय सुरक्षा सिस्टम्स के अतिरिक्त शिपमैन्ट शामिल हैं। जॉनसन ने कहा कि ''यू.के. की योजना अपने मित्रों के साथ काम कर यूक्रेन की सेना को प्रशिक्षित करने की है और प्रत्येक 120 दिन में 10 हजार सैनिक तैयार किए जाएंगे।''

रुस जहां पूर्वी यूक्रेन में क्रमिक रुप से बढ़त बना रहा है, वहीं जॉनसन ने भीषण युद्ध में रुस की सेना के क्षीण हो जाने पर यह कहते हुए जोर दिया कि रुस को अपना पुराना सैन्य सिस्टम बदलने के लिए वर्षों, शायद दशकों की जरुरत पड़ेगी, लेकिन रुस की सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर सैन्य उपकरण और गोलाबारुद इकट्ठा कर रही हैं कि शायद इतना जल्दी तो उसकी फैक्ट्रियों में इनका उत्पादन भी नहीं हो रहा होगा।

मई माह के अन्त में यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा था कि रुस की सैन्य यूनिट्स को सोवियत युग के असक्रिय टी-62 टैंकों से पुन: सुसज्जित किया गया है और लगता है कि ये टैंक पुराने स्टोर में से निकाले गए हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ''यू.के. और हमारे मित्रों को यह सुनिश्चित करते हुए प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि यूक्रेन के पास स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामरिक धैर्य हो और अन्तत: वह अपना संघर्ष जारी रखे।''

उन्होंने यूक्रेन की सहायता के लिए उठाए जाने वाले जरुरी कदमों के बारे में बताया। इनमें यह सुनिश्चित करते हुए यूक्रेन का संरक्षण कि उसे हथियार, सैन्य उपकरण, गोला-बारुद और सैन्य प्रशिक्षण इतनी शीघ्रता से मिले कि आक्रमणकारी इस सहायता से पहले अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि ना कर सके।

इसमें ब्लैक सी के रुस के मुख्य निर्यात मार्गो को अवरुद्ध कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने की उसे रोकने के लिए वैकल्पिक भू मार्ग विकसित करना शामिल है।

'हमें भी सुनें'

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जून। सेना में निचले स्तर के पदों पर भर्ती के लिए बनी अग्निपथ योजना की राह में कोई रोड़ा ना अटके इसके लिए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है कि स्कीम के खिलाफ दायर याचिका पर कोई भी आदेश देने से पूर्व उनका पक्ष सुना जाए।

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। एक याचिका में मांग की गई है कि रेल्वे सहित अन्य सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुंचाने और केन्द्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठित की जाए।

■ **केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि, अग्निपथ स्कीम पर निर्णय देने से पहले वे केन्द्रीय सरकार का पक्ष जरूर सुनें।**

याचिका में केन्द्र और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)